अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 116 | श्री विजय पुरम, मंगलवार, 29 अप्रैल 2025 | web: www. and.nic.in | 2.00 रूपए

तटीय राज्य मात्स्यिकी सम्मेलन 2025

माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने भातूबस्ती में थोक–सह–खुदरा मछली बाज़ार के निर्माण की वर्चुअल आधारशिला रखी

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग द्वारा आज मुंबई में आयोजित तटीय राज्य सम्मेलन 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज राज्य मंत्री श्री एस.पी. सिंह बघेल तथा भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन की उपस्थिति में श्री विजय पुरम के भातूबस्ती में थोक–सह–खुदरा मछली बाज़ार के निर्माण कार्य की आधारशिला पट्टिका का अनावरण किया।

कार्यक्रम में मछुआरों, मछली विक्रेताओं, मछुआरिनों, पीआरआई के प्रतिनिधियों और मत्स्य विभाग के अधिकारियों सहित 200 से अधिक हितधारकों की उत्साही और सक्रिय भागीदारी देखी गई। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना लगभग 750 वर्ग मीटर के भूखंड पर विकसित की जाएगी, जिसमें 300 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र होगा। क्षेत्र में मछली और मत्स्य उत्पादों के विपणन और वितरण को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया, प्रस्तावित मछली बाज़ार स्वच्छता, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। सुविधा की प्रमुख विशेषताओं में मछली के स्वच्छ प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक ऊंचा मंच, मछली काटने के लिए निर्दिष्ट अलग और विशाल क्षेत्र, स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक अच्छी तरह से कवर की गई जल निकासी प्रणाली और निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ओवरहेड पानी की टंकी शामिल होगी। इसके अतिरिक्त, मछली उत्पादों को संरक्षित करने के लिए पहले से तैयार कोल्ड स्टोरेज यूनिट, एक छोटा प्रशासनिक कार्यालय और शौचालय ब्लॉक जैसी आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। संरचनात्मक समर्थन के लिए एक रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाएगा और एक मोटर योग्य सड़क विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों के लिए मछली बाज़ार तक आसान पहुंच प्रदान करेगी। मछली उत्पादों की ताज़गी बनाए रखने के लिए उन्नत शीतलन उपकरण भी लगाए जाएंगे।

मत्स्य विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूरा होने पर, मछली बाज़ार से व्यक्तिगत विक्रेताओं और सहकारी समूहों सहित 80 से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए विपणन स्थान उपलब्ध कराने की उम्मीद है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह आसपास के क्षेत्र में लगभग 40,000 से 45,000 निवासियों की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करेगा, जिससे ताज़ी मछली और मत्स्य उत्पादों तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार होगा, साथ ही स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिलेगा और मत्स्य पालन क्षेत्र को मज़बूती मिलेगी।

माननीय उप राज्यपाल ने 'डीब्राइट' में दो दिवसीय अण्डमान तथा निकोबार सम्मेलन–एसएएनजीआईटीआई का शुभारम्भ किया

माननीय उप राज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश की उपलब्धियों को रेखांकित किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

दो दिवसीय अण्डमान तथा निकोबार सम्मेलन, एसएएनजीआईटीआई–2025 (सर्वे ऑफ अण्डमान एंड निकोबार गवर्नेन्स इनीशियेटीव्स फॉर ट्रांसफॉर्मेटीव आइलैंड्स), आज यहां के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) में शुरू हुआ। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी. के जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) ने अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार (आईएएस), नीति आयोग के अतिथि वक्ताओं, रक्षा एवं नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, पर्यटन हितधारकों एवं अन्य की उपस्थिति में पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर किया। सत्र की शुरुआत पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट के मौन के साथ हुई।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उप राज्यपाल ने कहा कि इस मंच की संकल्पना, विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को शामिल करते हुए खुली चर्चा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की एक महत्वपूर्ण पहल है और इसका वांछित उद्देश्य 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत विजन' को प्राप्त करना है, साथ ही 5 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था की ओर हमारा कदम और इस दिशा में केंद्र शासित प्रदेश का क्या योगदान हो सकता है।

उप राज्यपाल ने टिप्पणी की कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वीप अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को गति देने के लिए प्रमुख योजनाओं सहित विभिन्न सामाजिक–आर्थिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन जीवन की अच्छी गुणवत्ता की परिकल्पना करता है, जिससे 'ईज ऑफ बिजनेस', 'ईज ऑफ लिविंग' पहल, व्यक्तियों के लिए बिजली, पीने योग्य पानी, स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान सुनिश्चित होता है और प्रशासन ने एक जीवंत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज को सक्षम करने के लिए काफी अच्छा काम किया है।

मुख्यभूमि भारत के विपरीत, संघ शासित प्रदेश प्रशासन ने केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है और समय–समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन प्रक्रियाओं में तथा अधिकांश सामाजिक संकेतकों में तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से बेहतर प्रदर्शन किया है तथा राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर रैंकिंग भी प्राप्त की है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश को व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) में "दो नागरिक केंद्रित सुधार क्षेत्रों में शीर्ष उपलब्धि" के रूप में सुविधा प्रदान की गई थी। द्वीपों ने सबसे अधिक नियुक्ति पत्र जारी करके पहले और तीसरे रोज़गार मेलों में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि दो साल की अवधि में 5000 रिक्त पद भरे गए। इसके अलावा, सभी केंद्र शासित प्रदेशों और देश के राज्यों में, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह देश के पहले स्वच्छ सुजल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले स्थान पर रहा।

उप राज्यपाल ने कहा कि जून, 2017 के महीने में 'द्वीप विकास एजेंसी' की स्थापना के साथ कई परिवर्तनकारी बुनियादी ढाँचे हाथ में लिए गए है। कई दूरदर्शी और परिवर्तनकारी परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं जिनमें ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), हम्फ्री स्ट्रेट पर पुल, नया एयरपोर्ट टर्मिनल भवन शामिल हैं। उप राज्यपाल ने आगे बताया कि कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कोडल औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के विभिन्न चरणों में हैं। उप राज्यपाल ने कहा कि द्वीपों को विकसित करने की दृष्टि से, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पिछले कुछ वर्षों से द्वीपों के विकास पथ में पूर्ण बदलाव लाने के लिए कई प्रमुख परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है।

उप राज्यपाल ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को भारतीय महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख स्कूबा डाइविंग गंतव्य के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य सागर के भीतर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रयास करना है।

उप राज्यपाल ने विशेष रूप से पहलगाम की घटना के मद्देनज़र पर्यटकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया।

उप राज्यपाल ने अपने भाषण का समापन यह उल्लेख करते हुए किया कि विचार–विमर्श के परिणाम द्वीप क्षेत्र के समग्र विकास में परिवर्तनकारी बदलाव लाने में मदद करेंगे, इस क्षेत्र की दबावपूर्ण जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और सबसे आशाजनक उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे।

उप राज्यपाल ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पर्यटन ऐप भी लॉन्च किया और पर्यटन गतिविधि कैलेंडर जारी किया। उन्होंने सरकारी भवनों में स्थापित 'रूफ टॉप सोलार पावर प्लांट' का भी वर्चुअल उद्घाटन किया और इस अवसर पर 'दक्षता' कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव ने बताया कि पिछले दिसंबर में मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहा था, ताकि ज़मीनी स्तर पर अधिक से अधिक जुड़ाव हो और यह सम्मेलन उसी विशेष गतिविधि की की दिशा में है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य खुद को सार्थक जुड़ाव देना है, ताकि हमारे पास विकास से जुड़े विभिन्न विषयों और विभिन्न मुद्दों से संबंधित बहुत स्पष्ट उद्देश्य हों। यह सम्मेलन 7 व्यापक विषयों पर आधारित है, जैसे 1) पर्यटन, 2) जैव विविधता, 3) गतिशीलता, 4) ऊर्जा, 5) सामरिक सुरक्षा, 6) (क) जल, 6) (ख) सर्कुलर अर्थव्यवस्था, 7) (क) उत्पादन अर्थव्यवस्था–कृषि, 7) (ख) उत्पादन अर्थव्यवस्था–मत्स्य पालन। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि दो दिवसीय विचार–विमर्श निश्चित रूप से वित्तीय वर्ष–2025–2026 के लिए रोडमैप तैयार करने और भविष्य की योजना बनाने में मदद करेगा।

इससे पहले अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के आयुक्त श्री ए.एस.पी.एस. रविप्रकाश (आईएएस) ने सभा का स्वागत किया। उद्घाटन समारोह का समापन सचिव (योजना) डॉ. अमन गुप्ता (आईएएस) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

सम्मेलन 7 व्यापक विषयों पर आधारित है। आज, वक्ताओं ने पर्यटन, जैव विविधता, गतिशीलता और ऊर्जा जैसे विषयों पर विचार–विमर्श किया।

माननीय सांसद ने द्वीपों में सुनामी आश्रय आवंटियों को किरायेदारी अधिकार जारी करने का आग्रह किया

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल को लिखित अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें स्थायी सुनामी आश्रय आवंटियों को किरायेदारी अधिकार जारी करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। अनुरोध की एक प्रति भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को भी उनके नम्र अवलोकन और आवश्यक समर्थन के लिए भेजी गई है। अपने पत्र में श्री राय ने कहा है कि 2006 से 2009 के बीच कैम्पबेल बे, लिटिल अण्डमान, सीपीघाट, टेलराबाद, बर्मानाला, कालीकट, छोलदारी, नयाशहर, बम्बूफ्लाट और अन्य स्थानों पर निर्मित स्थायी सुनामी आश्रय स्थल प्रभावित परिवारों को आवंटित किए गए थे, जिन्होंने 2004 की सुनामी के दौरान जान–माल का भारी नुकसान उठाया था। ये आश्रय स्थल एनजीओ और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से बनाए गए थे।

सांसद कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि परिवारों को औपचारिक आवंटन आदेशों के माध्यम से आश्रय स्थल आवंटित किए गए थे और वे पिछले 16 वर्षों से पानी और बिजली जैसी उपयोगिता सेवाओं का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन कर रहे हैं, उन्हें मरम्मत या रखरखाव के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। नतीजतन, इनमें से अधिकांश आश्रय स्थल अब जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, जिनकी छतों, सीलिंग और संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी परेशानी को और बढ़ाने वाली बात यह है कि उनके कब्ज़े वाली ज़मीन (प्रति परिवार लगभग 200 वर्ग मीटर) पर किसी भी तरह का लिखित कानूनी हक़ या किरायेदारी अधिकार नहीं है। औपचारिक किरायेदारी के इस अभाव ने उन्हें बैंक ऋण लेने, विभिन्न सरकारी आवास योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने या स्वतंत्र रूप से मरम्मत और नवीनीकरण कराने के अवसर से वंचित कर दिया है।

अपने पत्र में श्री बिष्णु पद राय ने अनुरोध किया है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन, 1966 और संबंधित नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इन परिवारों को कब्ज़े वाली ज़मीनों पर लाइसेंस जारी करने के जरिए किरायेदारी अधिकार दिए जाएं। ऐसे अधिकार दिए जाने से प्रभावित परिवारों को अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने घरों को बनाए रखने और पुनर्निर्माण करने, वित्तीय और सरकारी सहायता प्रणालियों तक पहुंचने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का अधिकार मिलेगा।

हमें ही पहल करना होगा, फ़िज़ूल के खर्च की आदत को बदलना होगा।

उत्तर व मध्य अण्डमान जिले के पुलिस अधीक्षक ने बिल्लीग्राउंड में जन सुनवाई आयोजित की

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई पर ज़ोर दिया

श्री विजय पुरम 28 अप्रैल।

उत्तर व मध्य अण्डमान जिले की पुलिस अधीक्षक सुश्री यवेता के. सुगाथन (आईपीएस) ने आज स्थानीय निवासियों की शिकायतों को सीधे सुनने और उनका समाधान करने के लिए बिल्लीग्राउंड के हरि नगर के पंचायत हॉल में "जन सुनवाई" आयोजित की।

इस कार्यक्रम में बिल्लीग्राउंड क्षेत्र के लगभग 120 निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो स्थानीय नेताओं, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित समुदाय के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। बातचीत के दौरान, नागरिकों ने कानून प्रवर्तन चुनौतियों, सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं, यातायात प्रबंधन, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली अन्य नागरिक शिकायतों सहित कई तरह के मुद्दे उठाए। पुलिस अधीक्षक ने धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक प्रत्येक चिंता को सुना, जिन्होंने तत्काल प्रतिक्रिया दी, स्पष्टीकरण दिया और जहाँ भी संभव हो, मौके पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। संवादात्मक सत्र ने विश्वास और पारदर्शिता की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे पुलिस और समुदाय के बीच संबंध मजबूत हुए।

शिकायत निवारण सत्र के बाद, पुलिस अधीक्षक ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर जागरूकता संवाद भी आयोजित किया, जिसमें युवाओं और समाज पर नशीले पदार्थों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में जनता को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे नशीली दवाओं की लत न केवल व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करती है, बल्कि समुदायों के सामाजिक ताने–बाने को भी नष्ट करती है।

पुलिस अधीक्षक ने जनता से सतर्क रहने और नशीली दवाओं की गतिविधियों से संबंधित किसी भी जानकारी को तुरंत पुलिस के साथ साझा करने की अपील की और उन्हें पूर्ण गोपनीयता एवं त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तर व मध्य अण्डमान जिला पुलिस समुदाय के साथ घनिष्ठ जुड़ाव बनाए रखने और सुरक्षित, नशा मुक्त समाज सुनिश्चित करने के लिए जनता के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

विज्ञप्ति में आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी अपराध या अवैध गतिविधि से संबंधित कोई भी विश्वसनीय सूचना अपने नजदीकी पुलिस थाने या फोन नंबर 100, 112 और 03192–273344 पर दें। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा।

ग्रीष्मावकाश के दौरान दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए ब्रेल लिपि कक्षाएं

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

श्री विजय पुरम स्थित राज्य शिक्षा संस्थान, इस केंद्र शासित प्रदेश के 6 शैक्षणिक अंचलों में ग्रीष्मावकाश के दौरान दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले बच्चों (सीडब्ल्यूबीएलवी) के लिए ब्रेल लिपि कक्षाएं आयोजित करेगा, ताकि उन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाया जा सके, साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। ग्रीष्मावकाश के दौरान छह क्षेत्र संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अंचल का नाम	स्थान	समय
1	दक्षिण अण्डमान	ब्लॉक स्तरीय संसाधन कक्ष, जंगलीघाट स्कूल	सुबह 9 बजे से 11 बजे तक
2	विम्बर्लीगंज	ब्लॉक स्तरीय संसाधन कक्ष, कन्यापुरम स्कूल	
3	रंगत	ब्लॉक स्तरीय संसाधन कक्ष, बालिका छात्रावास, रंगत स्कूल	
4	डिगलीपुर	ब्लॉक स्तरीय संसाधन कक्ष, डिगलीपुर स्कूल	
5	कार निकोबार	ब्लॉक स्तरीय संसाधन कक्ष, तमालू स्कूल	
6	ननकौड़ी	ब्लॉक स्तरीय संसाधन कक्ष, गोल टेकरी स्कूल	

राज्य शिक्षा संस्थान की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले बच्चों से अनुरोध किया गया है कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठाएं।

विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 मनाया गया

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल।

देश के बाकी हिस्सों के साथ द्वीपों में भी 26 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय "पशु स्वास्थ्य के लिए टीम की आवश्यकता" था, जो पशु, मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए उनके सहयोगात्मक योगदान पर प्रकाश डालता है। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने किसानों, पालतू जानवरों के मालिकों, छात्रों और स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए द्वीपों में विविध गतिविधियों का आयोजन किया।

सभी जिलों में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम, कृमि मुक्ति अभियान और टीकाकरण अभियान चलाए गए। गोजातीय, बकरी, सूअर, कुत्ते और मुर्गी सहित 500 से अधिक जानवरों का इलाज, कृमि मुक्ति और टीकाकरण किया गया। एंटी–रेबीज़ टीकाकरण ने कई कुत्तों को सुरक्षित किया, जबकि एबीसी कार्यक्रमों ने प्री–स्क्रॉटल और इंट्राडर्मल स्यूटिंग जैसी उन्नत सर्जिकल तकनीकों का उपयोग करके कुत्तों और बिल्लियों को नपुंसक बनाया। किसानों को दवाइयाँ, खनिज मिश्रण और 600 वनराज चूजे दिए गए, ताकि घर के पिछले भाग में मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही चारा और अज़ोला की खेती पर प्रशिक्षण भी दिया जा सके।

पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनूठी पहलों में निबंध लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, कॅरियर परामर्श सत्र और पशु चिकित्सा कॅरियर के अवसरों पर प्रकाश डालने वाले जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। बाड़े में चारा खिलाने पर किसानों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को स्वास्थ्य और बांझपन शिविर के साथ–साथ प्रमाण पत्र और अंडे दिए गए। कर्मचारियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मीठाखाड़ी में 'शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों' पर चेतना लाई गई

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल।

नशामुक्त भारत अभियान के तहत 28 अप्रैल, 2025 को दक्षिण अण्डमान की मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम समाज कल्याण निदेशालय द्वारा पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) के सहयोग से आयोजित किया गया था। सत्र में शराब, तंबाकू और नशीली दवाओं के स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और समाज पर हानिकारक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें अपराध और सुरक्षा चिंताओं से उनके संबंध पर प्रकाश डाला गया। समाज कल्याण विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि चर्चाओं में पुनर्वास प्रक्रिया, सामाजिक मुद्दे और ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाने के तरीके, उपलब्ध सहायता प्रणाली और मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने और हल करने के तरीके भी शामिल थे।

अण्डमान तथा निकोबार जलक्षेत्र में समुद्री सीप पकड़ने का बंद मौसम

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण नियम, 2004 (17 (a) (ii) के अनुसार, 1 मई से 30 सितंबर–2025 तक की अवधि (प्रारंभ के दिन और समाप्ति के दिन को मिलाकर) अण्डमान तथा निकोबार जलक्षेत्र में समुद्री सीप पकड़ने का बंद मौसम होगा।

मत्स्य विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मछुआरों और विशेष रूप से, जो समुद्री सीप या मोलस्क निकालने में लगे हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे उत्तर व मध्य अण्डमान में समुद्री सीप पकड़ने के लिए उपरोक्त बंद मौसम का सख्ती से पालन करें।

एसबीएम एम्बेस्डर ने हैडो स्कूल का दौरा किया

श्री विजय पुरम 28 अप्रैल।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ–सफाई और स्वच्छता की जांच करने के लिए, पद्मश्री से विभूषित और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेस्डर श्री नरेश चंद्र लाल ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हैडो (हिंदी) का दौरा किया और छात्रों एवं शिक्षकों से बातचीत की, ताकि वे अपने स्कूल परिसर के साथ–साथ अपने संबंधित समाज में भी सफाई बनाए रख सकें।

प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने सभी छात्रों से खुद को हानिकारक पदार्थों से दूर रखने का अनुरोध किया और उन्हें खेल–खूद में शामिल होकर खुद को फिट रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने छात्रों को स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने पर भी ज़ोर दिया। श्री लाल ने सभी से पानी बचाने का अनुरोध किया। उप प्रधानाचार्य श्री आर. सेथुकराई दौरे के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेस्डर के साथ थे।

चिकित्सा अधिकारियों (प्रथम बैच) के लिए मातृ, नवजात शिशु देखभाल में सुधार के लिए दक्षता–प्रशिक्षण

श्री विजय पुरम 28 अप्रैल।

मातृ मृत्यु अनुपात और मृत जन्म दर को कम करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल, "दक्षता", 30 अप्रैल, 2015 को शुरू की गई थी, इस संबंध में अंतः और तत्काल प्रसवोत्तर अवधि के दौरान मातृ और नवजात शिशु देखभाल की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में इसे इन द्वीपों में लागू किया जा रहा है।

चिकित्सा अधिकारियों (प्रथम बैच) के लिए मातृ, नवजात शिशु देखभाल में सुधार के लिए दक्षता–प्रशिक्षण कार्यक्रम पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण 22 अप्रैल, 2025 से 24 अप्रैल, 2025 तक श्री विजय पुरम में उद्योग निदेशालय के सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया था।

संयुक्त सचिव आरसीएच–2 से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रशिक्षण का उद्घाटन स्वास्थ्य सेवा निदेशक (प्रभारी) डॉ. एच.एम. सिद्धाराजू ने किया और प्रोफेसर और एचओडी (प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ) डॉ. एम.के. साहा इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रोफेसर और एचओडी (प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ) डॉ. एम.के. साहा, प्रोफेसर और एचओडी (पीडियाट्रिक्स) डॉ. प्रगातेश, मायाबंदर में डॉ. आरपी अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी श्रीमती रूबी वर्गीस और जीबी पंत अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी श्रीमती प्रिविना, उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्ति थे। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से कुल 9 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

जन सुरक्षा और सहायता के लिए आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता

रंगत, 28 अप्रैल

मध्य अण्डमान के रंगत की एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) परियोजना ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी ब्लॉकों और आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रमुख हेल्पलाइनों पर एक समर्पित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। जागरूकता अभियान में पुलिस–100, फायर ब्रिगेड–101, एम्बुलेंस–102, महिला हेल्पलाइन–1091, चाइल्ड हेल्पलाइन–1098 आदि जैसी महत्वपूर्ण हेल्पलाइनों के महत्व और उपयोग पर प्रकाश डाला गया। अभियान का उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण सहायता सेवाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जनता को शिक्षित करना था।

रंगत के सीडीपीओ की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पहल को जनता से सक्रिय भागीदारी मिली और इसने आवश्यक हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

जहाज सिंधु की जगह एमवी छोलदारी 30 अप्रैल को डिगलीपुर जाएगा

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल।

यात्रियों/आम जनता को सूचित किया गया है कि तकनीकी कारणों से 30 अप्रैल, 2025 को श्री विजय पुरम से रात्रि 9 बजे मायाबंदर होते हुए जहाज सिंधु से डिगलीपुर के लिए घोषित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है।

हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए जहाजरानी सेवा निदेशालय ने जलयान एमवी छोलदारी को 30 अप्रैल, 2025 को रात्रि 8 बजे फीनिक्स बे जेटी से डिगलीपुर के लिए रवाना करने तथा 1 मई, 2025 को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजय पुरम के लिए रवाना करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है। जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एमवी छोलदारी की उपरोक्त यात्राओं के लिए यात्री टिकट 29 अप्रैल, 2025 (मंगलवार) से आम जनता को जारी किए जाएंगे। यात्री डीएसएस ई–टिकटिंग पोर्टल **(https://dss.andaman.gov.in/eticketing)** और स्टार्स टिकट काउंटर से सुबह 9 बजे से अपनी टिकटें बुक कर सकते हैं।

डीब्राइट–बीटेक मई/जून 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

श्री विजय पुरम, 28 अप्रैल

पांडिचेरी विश्वविद्यालय की 29 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाली बी–टेक मई/जून 2025 सैद्धांतिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा पंजीकरण 29 अप्रैल, 2025 और 5 मई, 2025 से शुरू किया जाएगा। 'डीब्राइट' की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बकाया पेपर वाले उत्तीर्ण छात्र और बी–टेक के नियमित छात्र, जो उक्त परीक्षा के लिए पात्र हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा पंजीकरण, परीक्षा शुल्क भुगतान और सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल परीक्षा से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए अपने संबंधित संकाय प्रभारी/शैक्षणिक समन्वयक/अपने विभाग के शैक्षणिक सदस्यों से संपर्क करें।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आधार प्रमाणीकरण की संख्या 2,707 करोड़ से अधिक हुई

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आधार प्रमाणीकरण की संख्या 2,707 करोड़ से अधिक हो गयी है। यह देश में बढ़ते डिजिटल भरोसे को दर्शाता है जो एक बडी उपलब्धि है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानि– यूआईडीएआई की प्रमाणीकरण सेवाओं, विशेष रूप से चेहरे के सत्यापन में काफी वृद्धि हुई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा है कि केवल मार्च 2025 में रिकॉर्ड तोड़ 44 करोड़ 63 लाख ई–केवाईसी का काम पूरा हुआ। यह सरकार की डिजिटल इंडिया पहल में, आधार की भूमिका को उजागर करता है।

यूआईडीएआई के प्रयासों और तकनीकी नवाचार को मान्यता देते हुए, प्राधिकरण को हाल ही में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार विशेष रूप से चेहरे के सत्यापन में सफलता के लिए दिया गया था, जिसका उपयोग अब बैंकिंग, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में किया जा रहा है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, छोलदारी की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

क्र.सं.	कार्य का नाम
1	एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/जीईएन/2024–25/211 छोलदारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत पंचायत भवन का नवीनीकरण। अनुमानित लागत : रु. 20,34,709/–, धरोहर राशि : रु. 40,694/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह। निविदा शुल्क : रु. 500/, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 05/05/2025 के अपराहन 3.00 बजे तक है। निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andaman.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं। टेंडर आई डी : 2025_RDPRI_18448_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

भारत ने कोविड–19 के दौरान करुणा के साथ नेतृत्व किया, वैश्विक स्तर पर 300 मिलियन टीके साझा किए : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक एशिया 2025 को संबोधित किया। श्री गोयल ने कोविड–19 महामारी के दौरान भारत की सक्रिय और दयालु वैश्विक प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला। वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से, भारत ने कम विकसित और कमजोर देशों को लगभग 300 मिलियन वैक्सीन खुराकें प्रदान कीं – जिनमें से कई निःशुल्क थीं – यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी देश पीछे न छूटे। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड–19 के दौरान निर्यात नियंत्रण लगाने वाले कई अन्य देशों के विपरीत, भारत ने वसुधैव कुटुम्बकम – दुनिया एक परिवार है के अपने प्राचीन लोकाचार पर खरा उतरते हुए सभी के लिए समान पहुँच को प्राथमिकता दी।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री गोयल ने आभार व्यक्त किया कि एशिया में पहली डब्ल्यूएचएस क्षेत्रीय बैठक स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सतत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच हासिल करने में भारत की यात्रा को साझा किया।

मंत्री ने महामारी के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ व्यक्तिगत बातचीत को याद किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से लाभ कमाने की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की।

स्वास्थ्य समानता के विषय को संबोधित करते हुए, श्री गोयल ने मामूली वृद्धिशील नवाचारों के माध्यम से दवा पेटेंट का विस्तार करने के प्रयासों की कड़ी आलोचना की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे लाखों लोग सस्ती दवाओं तक पहुंच से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे दूरदराज के क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के भारत के प्रयासों का प्रत्यक्ष अनुभव करें।

श्री गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 620 मिलियन से अधिक लोग मुत स्वास्थ्य देखभाल के लिए पात्र हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्रतिबद्धता कभी भी लाभ से प्रेरित नहीं रही, बल्कि करुणा से प्रेरित रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उद्धृत करते हुए श्री गोयल ने कहा, हमारे लिए स्वास्थ्य सेवा का मतलब सिर्फ बीमार मरीज का इलाज करना नहीं है। स्वास्थ्य सेवा निवारक स्वास्थ्य सेवा है, यह कल्याण है, यह मानसिक स्वास्थ्य सेवा है, और इसका मतलब है समाज को बेहतर जीवन शैली और बेहतर भविष्य के तहत जोड़ना।

केरल में "सेवोत्तम और लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण" विषय पर 5वीं राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। पारदर्शी और जवाबदेह शासन की आधारशिला के रूप में लोक शिकायतों के प्रभावी समाधान पर प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 25 अप्रैल, 2025 को केरल के सरकारी प्रबंधन संस्थान (आईएमजी) में 'सेवोत्तम और लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण' विषय पर 5वीं राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की।

सरकारी प्रबंधन संस्थान (आईएमजी) के निदेशक श्री के. जयकुमार, डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास, डीएआरपीजी की संयुक्त सचिव सुश्री जया दुबे और विभिन्न राज्यों के सरकारी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) और प्रशासनिक सुधार (एआर) विभागों के अन्य प्रतिभागियों की उपस्थिति में कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने मुख्य प्रस्तुति दी, जिसमें शिकायत निवारण में प्रमुख सुधारों की रूपरेखा बताई गई। इसमें भाषिणी के माध्यम से बहुभाषी समर्थन, उन्नत सीपीजीआरएएमएस सुविधाएं और मजबूत निगरानी शामिल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की संतुष्टि को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में एनआईसी और एनईजीडी के अलावा केरल सरकार, भारत सरकार, गैर–लाभकारी संस्थाओं और तकनीकी संगठनों के 18 वक्ताओं ने भाग लिया।

कार्यशाला पांच सत्रों में संपन्न हुई। कार्यशाला में से प्रत्येक में लोक शिकायतों में सर्वोत्तम प्रणालियों, प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग और शिकायत निवारण में गैर–लाभकारी संगठनों की भूमिका के बारे में पेशेवर उन्मुख प्रस्तुतियां शामिल थीं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) द्वारा अलग–अलग सत्र आयोजित किए गए, जिन्हें ज्ञान भागीदार के रूप में अपनी भूमिका में एटीआई के लिए मॉडल क्षमता निर्माण मॉड्यूल का सुझाव देना था। एएससीआई के प्रोफेसर निर्मलया बागची द्वारा सेवोत्तम नियमों के कुछ मसौदे को विभिन्न राज्य सरकारों के साथ चर्चा के लिए भी खोला गया था।

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव श्री चक्रवर्ती टी. कन्नन ने सीपीजीआरएएमएस में विकसित वर्गीकरण की संरचना और शिकायत दर्ज करने को सरल बनाने में इसके प्रभाव पर अंतर्दृष्टि साझा की। इससे प्रक्रिया अधिक सहज, सुलभ और नागरिक केंद्रित हो गई। उपरोक्त दोनों बिंदुओं पर सभी राज्यों के एटीआई और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए। केरल सरकार के प्रतिनिधियों में त्रिवेंद्रम की जिला कलेक्टर श्रीमती अनु कुमारी, प्रशासनिक सुधार की विशेष सचिव श्रीमती वीना माधवन और आईटी के विशेष सचिव श्री श्रीराम संबाशिव राव शामिल थे। भाषिणी के सीईओ श्री अमिताभ नाग, ई–गवर्नेंस फाउंडेशन के सीटीओ श्री के कृष्णकुमार, अगामी के टीम लीड श्री वरुण हेमचंद्रन और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर श्री निशीथ श्रीवास्तव ने भी कार्यक्रम में अपनी बात रखी। फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत सुधार, सर्वोत्तम प्रणाली, क्षमता निर्माण और सेवा वितरण को बढ़ाने तथा नागरिक संतुष्टि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभिनव समाधान शामिल थे।

पिछले वित्तीय वर्ष में 18 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में और 20 फरवरी, 2025 को भोपाल में 'लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण' पर 2 राष्ट्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) की भागीदारी थी।

आईटीआर के अलावा पैन कार्ड का होता है कई जगह इस्तेमाल, जानिए किन कामों में पड़ती है इसकी जरूरत

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। परमानेंट अकाउंट नंबर का इस्तेमाल आईटीआर फाइल करने के लिए किया जाता है। यह कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आज के समय में यह बहुत जरूरी दस्तावेज है। कई जगह इसका इस्तेमाल आईडी–प्रूफ के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा कई काम बिना पैन कार्ड के बगैर नहीं हो सकता है। पैन कार्ड ना होने पर कई सरकारी काम अटक भी जाते हैं। आइए, जानते हैं कि पैन कार्ड किन कामों के लिए जरूरी होता है।

बैंक अकाउंट ओपन करते समय भी हमें पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर हम बैंक अकाउंट में एक साथ 50 हजार रुपये डिपॉजिट करते हैं तब भी हमें पैन कार्ड की जानकारी देनी होती है। अगर होटल में भी 50,000 रुपये से ज्यादा का बिल आता है तब भी हमें पैन कार्ड की जानकारी देनी होती है।

वैवाहिक उत्सव (शादी–सगाई) में हमें लाखों की ज्वेलरी खरीदनी होती है। अगर आप एक साथ 2 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के गहने खरीदते हैं तब भी आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है।

अगर आप इस फेस्टिव सीजन गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। 5 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की गाड़ी खरीदने पर आपको कई डॉक्यूमेंट देने होते हैं। आपको पैन कार्ड भी देना होता है। इसके अलावा गाड़ी बेचते समय भी गाड़ी के दस्तावेज के साथ केवाईसी और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।

भारत में 5 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली प्रॉपर्टी खरीदने पर पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। इसके अलावा

प्रॉपर्टी बेचने पर भी पैन कार्ड की जरूरत होती है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए सेल्स डीड तैयार करना होता है। इसके लिए पैन कार्ड की जानकारी देनी होती है।

शेयर बाजार में 50 हजार रुपये से ज्यादा निवेश पर भी पैन कार्ड की जानकारी देनी जरूरी है। शेयर बाजार में डीमैट अकाउंट के जरिये निवेश किया जाता है। सेबी ने डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए ओरिजिनल पैन कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया है।

अगर आप कोई लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको लोन के आवेदन के साथ पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी लॉन्डरिंग को रोकने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिया कि बड़े ट्रांजेक्शन में ग्राहकों से पैन नंबर की जानकारी लेना अनिवार्य है।

आप विदेश घूमने जा रहे हैं तो फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए आप भारतीय करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए भी आपको पैन कार्ड की जानकारी देनी होती है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज में हो रही इनकम या फिर ट्रांजेक्शन में भी पैन कार्ड की जानकारी देनी होती है।

भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की दूसरी खेप सौंपी

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। भारत ने सोमवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप फिलीपींस को सौंप दी है। इसी के साथ भारत और फिलीपींस के बीच 2022 में किया गया अनुबंध पूरा हो गया है, जो 374 मिलियन डॉलर से अधिक का सबसे बड़ा और पहला विदेशी सौदा था। भारतीय वायु सेना के ताकतवर सी–17 ग्लोबमास्टर ने मिसाइल की खेप लेकर हिंडन एयरफोर्स से उड़ान भरी थी और अब यह विमान फिलीपींस वायु सेना के क्लार्क एयरबेस पर उतर चुका है।

ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (बीएपीएल) ने 28 जनवरी, 2022 को फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ तीन मिसाइलों के लिए एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। भारत से सुपरसोनिक मिसाइल खरीदने के लिए 374 मिलियन डॉलर से अधिक का यह सबसे बड़ा और पहला विदेशी सौदा था। भारत (डीआरडीओ) और रूस (एनपीओएम) के संयुक्त उद्यम ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस विकसित की है। ब्रह्मोस मिसाइल के सौदे पर भारत और फिलीपींस के बीच वर्षों से बातचीत चल रही थी। दोनों देशों ने 03 मार्च, 2020 को प्रमुख रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे।

भारत ने पिछले साल 19 अप्रैल को विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की पहली खेप के रूप में एक बैटरी फिलीपींस को सौंपी थी। इस ब्रह्मोस की रेंज 290 किमी (180 मील) है, जिसे जमीन, समुद्र और पनडुब्बी से दागा जा सकता है। दूसरी खेप की डिलीवरी ऐसे समय में हुई है, जब मनीला और बीजिंग के बीच कूटनीतिक और सुरक्षा संबंध दक्षिण चीन सागर में लगातार झड़पों के कारण तनावपूर्ण हैं। फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो टेओडोरो ने कहा कि भारत से खरीदी गई मिसाइल फिलीपींस सेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिससे चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच देश की तटीय रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी।

भारत के साथ मिसाइल का यह सौदा पूरा करने के बाद फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ दशकों से चल रहे क्षेत्रीय विवादों के साथ–साथ सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब फिलीपींस अपनी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए भारत से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के एक बैच खरीद रहा है। स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) 5.5 टन भार वर्ग में एक जुड़वां इंजन, बहु–भूमिका, बहु–मिशन नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है और इसे विभिन्न सैन्य अभियानों के लिए एक प्रभावी प्लेटफॉर्म माना जाता है।

फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। पिछले कुछ वर्षों के भीतर खासकर समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में तेजी आई है। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) का एक प्रमुख सदस्य भी है, जिसके साथ पिछले एक दशक में भारत के संबंधों में बड़ा विस्तार हुआ है। फिलीपींस ने भारत से आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी खरीदने के लिए रुचि दिखाई है। स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर का निर्यात बढ़ाने के प्रयासों के बीच आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली ने भारत को एयरोस्पेस की दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

ज्ञान पोस्ट पहल की शुरुआत, सस्ती दरों पर पोस्ट हो सकेगी अध्ययन सामग्री

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। भारतीय डाक ने 'ज्ञान पोस्ट' नामक नई पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इस सेवा से जुड़ी अधिसूचना जारी की। 'ज्ञान पोस्ट' का उद्देश्य सस्ती दरों पर किताबें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। यह विशेष रूप से दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों और शिक्षकों को लाभ पहुंचाएगी।

योजना की शुरुआत करते हुए आज संचार मंत्री सिंधिया ने कहा कि इससे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक किताबें हर कोने में पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शैक्षणिक संसाधन युवाओं तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को आगे रखते हुए कहा कि हमारा पोस्ट ऑफिस इस लक्ष्य में योगदान देने के लिए सक्षम है।

इस संबंध में जारी अधिसूचना के डाकघर से जुड़े नियमों में संशोधन के तहत एक नई सेवा 'ज्ञान पोस्ट' शुरू की गई है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक साहित्य तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों को विशेष नियमों के तहत सस्ती दरों पर भेजा जा सकेगा। ज्ञान पोस्ट के तहत भेजे जाने वाले पैकेट पर 'ज्ञान पोस्ट' अंकित होना अनिवार्य होगा और इसमें व्यावसायिक या नियमित प्रकाशन जैसे पत्रिका आदि सम्मिलित नहीं किए जा सकते।

ज्ञान पोस्ट के अंतर्गत बुकिंग की न्यूनतम वजन सीमा 300 ग्राम और अधिकतम 5 किलोग्राम तय की गई है। ये पैकेट ट्रैक होंगे। इन्हें जमीनी मार्ग से भेजा जाएगा और निरीक्षण के अधीन रहेंगे। शुल्क संरचना वजन के अनुसार तय की गई है, जैसे 300 ग्राम तक के लिए 20 रुपये और 4–5 किलोग्राम तक के लिए 100 रुपये होंगे।

भारत से नेपाल जाने के लिए अब आधार कार्ड या पहचान–पत्र आवश्यक होगा।

पश्चिम चम्पारण (बगहा),28 अप्रैल। भारत–नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के वाल्मीकिनगर बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल 21वीं वाहिनी गंडक बराज के अधिकारियों द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमला के बाद सुरक्षा कारणों से व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अब किसी भी भारतीय नागरिक को नेपाल जाने से पहले उसे अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पहचान–पत्र दिखाना होगा। बिना पहचान– पत्र के किसी भी व्यक्ति को भारतीय सीमा से नेपाल क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

गंडक बाराज पर तैनात सहायक कमांडेंट जयंत बोरा ने बताया कि कमांडेंट तापेश्वर राऊत के दिशा– निर्देश पर सुरक्षा बिंदुओं को ध्यान में रखकर नेपाल जाने वाले सभी लोगों को आईडी प्रूफ दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है, बिना आईडी प्रूफ नेपाल जाने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि वाल्मीकि नगर सीमा क्षेत्र में चौक चौराहों पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों को तैनात किया गया है, जिससे किसी भी संदिग्ध और अजनबी गतिविधि पर विराम लगेगी। उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील किया है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को देखने के बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस या सशस्त्र सीमा बल को अपना मित्र मानकर बिना डरे सूचित करें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।

इतिहास के पन्नों में 29 अप्रैलः दिल्ली में लाल किला की नींव रखी गई

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। देश–दुनिया के इतिहास में 29 अप्रैल की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। यह तारीख दिल्ली के लाल किला के लिए बेहद खास है। यह लाल बलुआ पत्थर से बनी एक खूबसूरत इमारत है। पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां के तामीर कराए गए इस ऐतिहासिक लाल किले को वर्ष 2007 में युनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना। शानदार गुंबदों, बेहतरीन मेहराबों और जालीदार छज्जों से सजी यह इमारत, बेहतरीन स्थापत्य कला और बेमिसाल कारीगरी का नमूना है। भारत के इतिहास में इसके महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद से हर वर्ष 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किला की नींव 1639 में 29 अप्रैल को ही रखी गई थी। महत्वपूर्ण घटनाचक्र– 1661–चीन के मिंग वंश ने ताइवान पर कब्जा किया।

1639– दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई।

1813– अमेरिका में जेएफ हम्मेल ने रबर का पेटेंट कराया।

1903– महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल हाई कोर्ट में लीगल प्रैक्टिस शुरू की और वहां ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की।

1930– ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत।

1939– नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया।

1978– अफगानिस्तान के विद्रोही गुट ने सत्ता हासिल की। काबुल रेडियो पर घोषणा की गई कि उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वायुसेना अध्यक्ष लड़ाई में मारे गए।

1991– बांग्लादेश के चटगांव में आए चक्रवाती तूफान में एक लाख 38 हजार लोग मारे गए और 10 लाख लोग बेघर हो गए।

1993– पहली बार बकिंघम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया। इसे देखने के लिए आठ पाउंड का टिकट तय किया गया।

1997– रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लागू।

2007– आस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार क्रिकेट विश्वकप जीता।

2008– ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद भारत पहुंचे।

2008– तिब्बत में मार्च 2008 में भड़की हिंसा के सिलसिले में स्थानीय अदालत ने 17 लोगों को तीन साल कैद की सजा सुनाई।

2010– भारत ने दुश्मनों के रडार की पकड़ में नहीं आने वाले मुंबई की मंझगांव गोदी में निर्मित आधुनिकतम उपकरणों से लैस युद्धपोत आईएनएस शिवालिक को नौसेना में शामिल किया।

2010– भारतीय इंजीनियर हरपाल कुमार ने लंदन में आंत में कैंसर के शिकार लोगों का ब्लड टेस्ट कर रोग का पता लगाने के बजाय उनके पेट का निरीक्षण कर सकने वाले कैमरे का आविष्कार किया।

2011– लंदन के ऐतिहासिक चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में ब्रिटिश राजकुमार विलियम और केट मिड्लटन का विवाह हुआ।

भारत–फ्रांस के बीच 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा पूरा

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

भारत–फ्रांस के बीच 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सोमवार को 63 हजार करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर हो गए। नई दिल्ली में भारत में फ्रांस के राजदूत के बीच हुए इस सौदे से भारतीय नौसेना की लड़ाकू ताकत और ज्यादा मजबूत होगी। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया, जबकि नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन भी मौजूद थे।

भारत और फ्रांस ने आज 26 राफेल मरीन विमान खरीदने के लिए 63 हजार करोड़ रुपये के बड़े सौदे पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने इसी माह 09 अप्रैल को फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दी थी। इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल–सीटर और चार ट्विन–सीटर विमान मिलेंगे। इससे भारतीय नौसेना की लड़ाकू ताकत और ज्यादा मजबूत होगी। फ्रांस को अनुबंध के तहत सौदे पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 37 महीनों के भीतर पहला राफेल मरीन विमान देने की बाध्यता होगी।

भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के लिए बोइंग एफ/ए–18 सुपर हॉर्नेट की जगह फ्रांसीसी राफेल मरीन को चुना है। भारत और फ्रांस के बीच इस बारे में लम्बे समय से चल रही बातचीत पूरी हो चुकी है। पहले इस वित्तीय वर्ष में ही सौदे पर हस्ताक्षर करने की योजना थी, लेकिन संसद के बजट सत्र के कारण इसमें देरी हुई है। भारतीय नौसेना के मल्टी–रोल कैरियर बोर्न फाइटर के लिए आपातकालीन खरीद नीति के तहत सरकार–से–सरकार सौदे के माध्यम से 26 एयरफ्रेम प्राप्त किए जाएंगे। पहले इस तरह के 57 विमान खरीदे जाने थे, लेकिन बाद में यह संख्या घटाकर 26 कर दी गई है।

भारत की जरूरतों के लिहाज से फ्रांसीसी कंपनी ने परमाणु सक्षम एक श्राफेल मरीनश स्की–जंप करने की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए भारत भेजा था। विमानवाहक आईएनएस विक्रांत के लिए भारतीय नौसेना ने पिछले साल जनवरी में गोवा स्थित आईएनएस हंसा में समुद्री लड़ाकू विमान श्राफेल मरीनश का परीक्षण किया था। वायु सेना के राफेल जेट और समुद्री संस्करण राफेल मरीन में एक अंडरकारेज और नोज व्हील, एक बड़ा अरेस्टर हुक, एक एकीकृत सीढ़ी जैसे कई अन्य मामूली अंतर हैं। राफेल मरीन स्की टेक–ऑफ के लिए चार–पांच टन तक बाहरी भार (पूर्ण आंतरिक ईंधन के साथ) ले जा सकता है।

राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन को भरोसा है कि राफेल एम भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के लिए उपयुक्त होगा। राफेल एम का इस्तेमाल अभी भी ग्रीस, इंडोनेशिया और यूएई की सेनाएं कर रही हैं। भारतीय नौसेना का मानना है कि राफेल उसकी जरूरतों को काफी बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। भारतीय नौसेना 43 पुराने रूसी फाइटर जेट मिग–29के और मिग–29के यूबी को अपने बेड़े से हटाना चाहती है।

खरीफ की बुआई से पहले सभी केवीके और आईसीएआर किसान जागरूकता अभियान चलाएं: केंद्रीय कृषि मंत्री

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में देशभर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) से वर्चुअल संवाद किया। उनकी पहल पर आयोजित इस अभिनव संवाद कार्यक्रम में सभी केवीके के चल रहे प्रयासों, उनकी भूमिका और भावी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को लेकर व्यापक चर्चा हुई।

इस दौरान शिवराज सिंह ने सभी केवीके से किसानोन्मुखी प्रयासों में तेजी लाने की बात कही। साथ ही कहा कि खेती–किसानी की उन्नति में केवीके सशक्त माध्यम के रूप में भूमिका निभाएं। केवीके कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, इसलिए खरीफ की बुआई से पहले सभी केवीके और आईसीएआर राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसान जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और किसानों के हितों के मद्देनजर उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले केवीके को पुरस्कृत किए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ।

इस संवाद में देशभर के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रमुखों के साथ ही कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए, जिनमें से कुछ ने केवीके की उपलब्धियां बताईं और अपने सुझाव भी दिए। आईसीएआर–कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (अटारी) जोधपुर (राजस्थान), अटारी हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), अटारी पटना (बिहार), अटारी जबलपुर (मध्य प्रदेश) के अलावा मंडी (हिमाचल प्रदेश), नंदूरबार (महाराष्ट्र), खुर्दा (ओडिशा), मोरीगांव (असम) और लक्षद्वीप के केवीके प्रमुखों ने अपने–अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार अपने कामकाज, उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री को जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट और उप महानिदेशक (प्रसार) डॉ. राजबीर सिंह ने प्रारंभ में केवीके के संबंध में रूपरेखा बताई।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अभियान स्वरूप कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यापक क्षेत्र है। प्रत्यक्ष रूप से लगभग 45: आबादी कृषि से जुड़ी है और हमारी जीडीपी का लगभग 18: हिस्सा कृषि क्षेत्र से ही आता है, इसलिए इस व्यापक भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमें लगातार प्रभावशाली प्रयास करने होंगे। केवीके प्रमुखों को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अच्छे प्रशिक्षण और जागरुकता के माध्यम से हम किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकते हैं।

चौहान ने कृषि के लिए 6 सूत्री रणनीति, जिसमें उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, फसलों के ठीक दाम, नुकसान की भरपाई, खेती का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती शामिल है, उसके बारे में भी मार्गदर्शन किया। खाद्यान्न उत्पादन के लिए बेहतर बीजों, नए शोध, नई तकनीकों के प्रयोग पर बल देते हुए शिवराज ने इसी क्रम में और अधिक मॉडल फार्म बनाने और नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के माध्यम से भी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम के परिवार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपे उनके निजी कागजात

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के परिवार वालों ने उनके कुछ जरूरी कागजात भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) को सौंपे। इनमें मूल पत्राचार, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यात्रा रिपोर्ट और विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ–साथ संगठनों में डॉ कलाम द्वारा दिए गए व्याख्यान से जुड़े कागजात शामिल हैं।

दिल्ली स्थित एनएआई में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में डॉ. कलाम की भतीजी डॉ. एपीजेएम नाजमा मरैकयार और डॉ. कलाम के पोते एपीजेएमजे शेख सलीम ने पूर्व राष्ट्रपति के कुछ जरूरी कागजात एनएआई को सौंपें। इस मौके पर एनएआई के महानिदेशक अरुण सिंघल ने डॉ. एपीजेएम नाजमा मरैकयार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर महानिदेशक सिंघल ने कहा कि अब आम लोग भी डॉ. कलाम के 1000 से अधिक भाषणों के संग्रह को देख और पढ़ सकेंगे। सभी कागजात का डिजिटलीकरण किया जाएगा। आने वाली पीढ़ी एनएआई के निजी संग्रह में जाकर डॉ. कलाम, महात्मा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्रबोस द्वारा लिखे पत्र और दस्तावेज पढ़ सकती है।

एनएआई के सहायक निदेशक डॉ. मानस मिश्रा ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि आज औपचारिक तौर पर डॉ कलाम और एनएआई के बीच समझौता किया गया। इसके तहत परिवार वालों ने डॉ कलाम के निजी पत्राचार, भाषणों का संग्रह, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को एनएआई को सौंपा। इसके लिए एनएआई की टीम दिल्ली से रामेश्वरम डॉ. कलाम के घर पर उनके निजी पत्रों को लेने के लिए पहुंची थी। टीम में उनके साथ उपनिदेशक राजू सिंह और सहायक निदेशक डॉ. रिचा थे।

डॉ कलाम द्वारा लिखे लेक्चर, पत्रों से भरे 12 बॉक्स को चार बड़ बॉक्स में भर कर दिल्ली लाया जा रहा है। डॉ कलाम द्वारा विश्वविद्यालयों में दिए गए भाषणों का संकलन है जिसमें विकसित भारत का रोडमैप का विजन है। इन सभी भाषणों को अब अभिलेखागार में रखा जाएगा और उनका डिजीटलीकरण किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि डॉ. कलाम (1931–2015), जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, एक प्रख्यात वैज्ञानिक और देश के राष्ट्रपति (2002–2007) थे। डॉ. कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ। उन्होंने अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ी जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। एनएआई भारत सरकार के गैर–वर्तमान अभिलेखों का संरक्षक है। सार्वजनिक अभिलेखों के अपने विशाल संग्रह के अलावा एनएआई में सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित भारतीयों के निजी कागजात का एक समृद्ध और लगातार बढ़ता हुआ संग्रह भी है, जिन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ ओटीटी और सोशल मीडिया कंपनियों को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी किया है। यह कदम एक जनहित याचिका पर उठाया गया है जिसमें मांग की गई है कि ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा कि याचिका ने महत्वपूर्ण चिंता का मुद्दा उठाया है। कोर्ट ने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ऑल्ट बालाजी, उल्लू, एएलटीटी, एक्स, मेटा इंक (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी), गूगल, मुबी, एप्पल और अन्य से इस विषय पर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री बिना किसी नियमन या जांच के प्रसारित हो रही है। इस पर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अश्लील कंटेंट केवल कुछ विशेष कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई नियमित कार्यक्रमों में भी इस तरह की सामग्री मौजूद है। उन्होंने कहा, "कुछ कार्यक्रम इतने विकृत हैं कि दो सभ्य पुरुष भी साथ बैठकर इन्हें नहीं देख सकते।" उन्होंने जानकारी दी कि कुछ नियंत्रण पहले से मौजूद हैं और कुछ और नियमों पर काम हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह याचिका ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अश्लील और अभद्र सामग्री के प्रदर्शन से जुड़ी एक "महत्वपूर्ण चिंता" को उठाती है। कोर्ट ने माना कि याचिका में उठाए गए मुद्दे नीति निर्माण के दायरे में आते हैं और यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस पर विचार करे। इसलिए कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह याचिका उदय माहुरकर, संजीव नेवर, सुदेशना भट्टाचार्य मुखर्जी, शताब्दी पांडे और स्वाति गोयल ने मिलकर दायर की है।

याचिका में मांग की गई है कि एक स्वतंत्र समिति या प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज करें और जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हों।

भारत ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों पर लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने के आरोप में पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनके कुल 63 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यह प्रतिबंध गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद लगाया गया है और इसमें प्रमुख समाचार आउटलेट और पत्रकार शामिल हैं।

प्रतिबंधित किए गए प्लेटफॉर्म में समाचार आउटलेट डॉन, समा टीवी, एआरवाई न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, जियो न्यूज और सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल शामिल हैं। पत्रकार इरशाद भट्टी, अस्मा शिराजी, उमर चीमा और मुनीब फारूक के यूट्यूब चैनल भी प्रतिबंधित किए गए हैं। जिन अन्य हैंडल पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें द पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, उजैर क्रिकेट और रजी नामा शामिल हैं।

इसके साथ सरकार ने बीबीसी को भी उस शीर्षक पर चेतावनी दी है, जिसमें लिखा था, पाकिस्तान ने कश्मीर में पर्यटकों पर हुए घातक हमले के बाद भारतीयों के लिए वीजा निलंबित कर दिया है। बीबीसी ने स्टोरी में आतंकवादी को मिलिटेंट बताया है।

सरकार के मुताबिक ये यूट्यूब चैनल पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे, भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पहलगाम आतंकी हमले में 25 पर्यटकों और एक कश्मीरी की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी।

आईआईटी जोधपुर में यूएवी और ड्रोन पर होगी रिसर्च

जोधपुर, 28 अप्रैल।

भारतीय सेना ने अपनी सामरिक रणनीति में एक आयाम जोड़ते हुए भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर में पृथ्वी मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है। इसके साथ ही यहां राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए मानेकशॉ उत्कृष्ट केंद्र की भी शुरुआत की गई है। इसके तहत शिक्षाविद, रक्षा विशेषज्ञ और उद्योग मिलकर देश की सुरक्षा के लिए तकनीक पर काम करेंगे। आईआईटी में मानव रहित विमानों (यूएवी) की तकनीक, ड्रोन हमलों व राष्ट्रीय सुरक्षा में ड्रोन के बेहतर उपयोग से जुड़ी तकनीक पर शोध के अलावा ऊर्जा हथियारों पर अनुसंधान किया जाएगा।

देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और स्वदेशी नवोन्मेष को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश के बड़े शैक्षणिक संस्थान मानेकशॉ राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन और अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक साथ जुड़े हैं, जिसमें आईआईटी जोधपुर भी शामिल हुआ है। भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की ओर से समर्थित यह नोडल केंद्र रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान, नवोन्मेष और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस दौरान सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने कहा कि भारत के पास एनर्जी है, उसे सिनर्जी की जरूरत है। उन्होंने सैनिक और वैज्ञानिक, कमांडर और कोडर के संदर्भ में कहा कि यह एक पथ प्रदर्शक पहल हैं और यह हमें बहुत आगे ले जाएंगे। भारत में ऊर्जा है, लेकिन भारत को तालमेल की आवश्यकता है और हमें इसे आगे ले जाना है। यह संपूर्ण अभिसरण सैनिक और वैज्ञानिक, कमांडर और कोडर और नीति निर्माता और प्रोटोटाइप के बीच होना चाहिए। हमें एक राष्ट्र के रूप में 4–5 ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां हम विश्व के सिरमौर होंगे।

इस मौके पर आईआईटी के निदेशक प्रो. अविनाश अग्रवाल ने कहा कि यह गौरव का क्षण है, क्योंकि हमने मानेकशॉ सेंटर की पहली संवाद श्रृंखला की मेजबानी की। इसके तहत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा भविष्य को आकार देने के लिए सशस्त्र बल, शिक्षाविद और उद्योग एक मंच पर आए हैं। मानेकशॉ सेंटर केवल एक सेंटर नहीं है, यह एक विजन है, जिसे एक्शन में तब्दील किया गया है। केंद्र का उद्देश्य उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के समाधान विकसित करने के लिए शिक्षाविदों, रक्षा विशेषज्ञों और उद्योग के बीच अंतः विषय सहयोग को बढ़ावा देना है।

अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आजः जाने इतिहास, महत्व और नृत्यों के विभिन्न रूपों के प्रकार

नई दिल्ली, 28 अप्रैल।

नृत्य केवल एक कला नहीं है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 30 मिनट की डांस क्लास जॉगिंग सेशन के बराबर होती है। यह सबसे बेहतरीन और सबसे मजेदार फिटनेस एक्सरसाइज में से एक है जिसमें भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं होती, कोई दर्दनाक स्ट्रेचिंग आदि नहीं होती। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नृत्य के कई फायदे हैं और यह आराम करने का एक शानदार तरीका है। हर साल 29 अप्रैल को कला के इस खूबसूरत रूप का जश्न मनाने और वैश्विक स्तर पर अन्य नृत्य रूपों को संजोने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है।

इस दिन नृत्य को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसे यूनेस्को के प्रदर्शन कलाओं के मुख्य भागीदार, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान (आईटीआई) की नृत्य समिति द्वारा बनाया गया था। 29 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह प्रसिद्ध फ्रांसीसी नृत्य कलाकार जीन–जॉर्जेस नोवरे का जन्मदिन है, जिनका जन्म 1727 में हुआ था, जो एक बैले मास्टर और नृत्य के महान सुधारक थे।

यूनेस्को द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के निर्माता और आयोजक आईटीआई हैं। आपको बता दें कि 1982 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस बनाया गया था और तब से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के लिए संदेश लिखने के लिए एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व का चयन किया जाता है। यहां तक कि आईटीआई, एक चयनित मेजबान शहर में एक प्रमुख कार्यक्रम बनाता है जहां कई नृत्य प्रदर्शन, शैक्षिक कार्यशालाएं, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भाषण, नृत्य कलाकार, मानवीय परियोजनाएं आदि होती हैं।

इसके अलावा दुनिया भर में खुले दरवाज़े पर पाठ्यक्रम, प्रदर्शनियां, लेख, स्ट्रीट शो, विशेष प्रदर्शन आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को विश्व नृत्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है, और 'नृत्य की कला' के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाता है। यह नृत्य के कई रूपों और कला के रूप में उनके महत्व के बारे में शिक्षा भी फैलाता है।

मूल रूप से, यह दिन दुनिया भर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और त्यौहारों के माध्यम से नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। नृत्य दुनिया भर की संस्कृतियों में एक कला रूप और संचार का एक तरीका है और लाखों लोग इसका अभ्यास करते हैं।

हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह दिन उन लोगों के लिए उत्सव है जो नृत्य और इसके कला रूपों को महत्व देते हैं और यह उन अन्य लोगों, संस्थानों आदि के लिए एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करता है, जिन्होंने अभी तक इसके मूल्य को नहीं पहचाना है।

1. ओडिसी नृत्य शैली– यह नृत्य की एक शुद्ध शास्त्रीय शैली है, जो मनमोहक मुद्राओं से समृद्ध है। इस नृत्य शैली में कहानी कहने का तत्व है जिसकी जड़ें ओडिशा के मंदिरों में हैं।

2. भरतनाट्यम नृत्य शैली– यह सबसे पुरानी शास्त्रीय प्रदर्शन कलाओं में से एक है जिसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया जाता है। आपको बता दें कि नृत्य की इस शैली की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी।

3. समकालीन नृत्य शैली– नृत्य का यह रूप आजकल प्रचलन में है और यह भी थीम–शैली नृत्य से जुड़ा हुआ है।

4. नवशास्त्रीय नृत्य शैली– यह प्रदर्शन कला का नवीनतम रूप भी है। इसे 2019 की वर्तमान पीढ़ी से मेल खाने वाली आधुनिक शैली के रूप में भी जाना जाता है।

5. तांडव नृत्य शैली– शिव तांडव नृत्य शैली की जड़ें पौराणिक हैं जो भगवान शिव से संबंधित हैं और उन्हें विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है।

6. कुचिपुड़ी नृत्य शैली– यह भी शास्त्रीय नृत्य का एक अन्य रूप है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है।

7. कथक नृत्य शैली– इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आज तक भारत में सबसे ग्लैमरस शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है।

8. छऊ नृत्य शैली– यह मंचीय नृत्य का एक अर्ध–शास्त्रीय रूप है और इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में हुई।

9. कथकली नृत्य शैली– यह नृत्य की एक शानदार मंचीय कला है। इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के दक्कन भाग से हुई है। यह केरल की एक शानदार कला है। इसे भारत के सबसे कठिन नृत्य रूपों में से एक माना जाता है।

10. मणिपुरी नृत्य शैली– जैसा कि नाम से पता चलता है, इस नृत्य शैली की उत्पत्ति देश के पूर्वोत्तर भाग मणिपुर में हुई थी। यह एक जीवंत शास्त्रीय नृत्य है जो भारतीय देवी–देवताओं की शुद्ध भारतीय पौराणिक कहानियों के इर्द–गिर्द घूमता है।

अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या विश्व नृत्य दिवस दुनिया भर में आम जनता के बीच नृत्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर की सरकारों को शिक्षा की सभी प्रणालियों में नृत्य को उचित स्थान प्रदान करने के लिए राजी करना भी है।